इन्वेस्ट यूपी स्थापित करेगा जापान डेस्क

- जापानी कंपनियों के निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति दिलाने में मदद करेगी डेस्क
- ओसाका वर्ल्ड एक्सपो से उप्र के प्रतिनिधिमंडल के लौटने पर कदम उठाने का निर्णय

राज्य ब्यूरो, जागरण● लखनऊ: उत्तर प्रदेश में जापानी निवेश बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट यूपी जापान डेस्क की स्थापना करेगा। इसके लिए इन्वेस्ट यूपी ने अधिकारियों का चयन शुरू कर दिया है। इन्हें जापानी भाषा का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। यह अधिकारी निवेश प्रस्तावों के संदर्भ में जापानी कंपनियों से लगातार संपर्क में रहेंगे। जापानी कंपनियों से प्राप्त होने वाले निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति दिलाएंगे। निवेश से जुड़ी प्रक्रिया में जापानी कंपनियों की मदद करेंगे।

इन्वेस्ट यूपी के माध्यम से पिछले माह जापान गए उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने ओसाका शहर में चल रहे वर्ल्ड एक्सपो में भाग लेने के अलावा विभिन्न क्षेत्रों में काम रहीं जापानी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उन्हें प्रदेश में निवेश का न्योता दिया है। एक्सपो में उत्तर प्रदेश ने अपना पैवेलियन स्थापित किया है। इस पैवेलियन में ओडीओपी उत्पादों को भी प्रदर्शित किया गया है। मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी के साथ इन्वेस्ट यूपी के सीईओ विजय किरन आनंद सहित पांच अधिकारियों की टीम ने जापान के यामानाशी प्रांत स्थित ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, संटोरी हकुशू डिस्टलरी व हाइड्रोजन रिसर्च केंद्र, यामानाशी विश्वविद्यालय में स्थापित हाइड्रोजन और ईंधन सेल नैनोमैटीरियल्स केंद्र का दौरा किया था।

इन्वेस्ट यूपी की टीम ने जापानी प्रतिनिधियों को उप्र में निवेश और तकनीकी हस्तांतरण का प्रस्ताव दिया है। टोक्यो इलेक्ट्रान लिमिटेड के साथ सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में निवेश व तकनीकी सहयोग का भी प्रस्ताव जापानी कंपनी को दिया गया है। जापान की डेंसो कारपोरेशन को भी मोटर जेनरेटर निर्माण इकाई की स्थापना का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा जापान के विभिन्न शहरों के मेयरों के साथ शहरी विकास को लेकर भी प्रतिनिधिमंडल ने चर्चा की है। जापान की कई फार्मा कंपनियों को भी निवेश के प्रस्ताव दिए गए हैं। जापानी कंपनियों ने उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश में रुचि दिखाई है। इसीलिए इन्वेस्ट यूपी जापान डेस्क की स्थापना कर रहा है, जिससे निवेश के प्रस्तावों को जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जा सके।

खाद्य प्रसंस्करण में 700 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी

राज्य में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में 700 करोड़ रुपये का निवेश हो रहा है। इसके लिए कंपनियों-इकाइयों को 150 करोड़ रुपये का अनुदान मिलेगा। राज्य स्तरीय इम्पावर्ड समिति की बैठक में 52 निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इनमें गुजरात, राजस्थान, हरियाणा व उत्तराखंड के उद्यमियों द्वारा रामपुर में लगभग 300 करोड़ रुपये का निवेश कर मटर, गाजर, गोभी, पालक, मशरूम आदि के प्रसंस्करण की इकाइयां स्थापित की जा रही हैं। कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई उप्र खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 तहत गठित राज्य स्तरीय इम्पावर्ड कमेटी की बैठक में 54 प्रस्ताव परीक्षण व निर्णय के लिए प्रस्तुत किए गए।